RAJYA SABHA

Friday, the 30th August, 1991/Bhadra 8, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, there should be an obituary on the Communist Party of the Soviet Union. They have decided to wind it up after 70 years. It is a major event and we should have an obituary read out on the Communist Party.

MR. CHAIRMAN: Question No. 81.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई में कमी

*81. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली में इस समय वितरित किये जा रहे दूध की मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में दिल्ली में डी एम०एस० दूध की सप्लाई में कोई कमी आने की संभावना है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के मूल्यों में बढ़ोतरी किये जाने की संभावना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) The Delhi Milk Scheme (DMS) distributes approximately 4.5 lakh litres of milk per day in Delhi.

(b) No, Sir.

(c) the pricing of DMS milk is under review, taking into account the current cost of production and other relevant factors. Details are being worked out.

डा० रत्नाकर पांडेय : माननीय सभापति जी इस समय दिल्ली में दूध की कुल खपत जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 4.5 लाख लीटर है। इसमें मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली दुग्ध योजना का कितना योगदान है और कितना प्राइवेट सेक्टर से दूध लिया जाता है ? या यह सही नहीं है कि दिल्ली दुग्ध योजना केवल प्राइवट कोआपरेटिव्ज से ही दूध लेती है ? यदि यह सही है तो इस समय कुल कितने प्राइवेट कोआपरेटिव्ज दिल्ली मिल्क स्कीम को दूध मुहैया कर रहे हैं ? यह दूध किन शर्तों पर लिया जाता है और यदि किसी कांट्रैक्ट पर लिया जाता है तो उसकी अवधि क्या है ? अगर अवधि से पहले प्राइवेट कोआपरेटिव दूध सप्लाई करने के दामों में बढोतरी चाहती है या पूरा दूध मुहैया नहीं करती है तो सरकार उनके खिलाफ कांट्रैक्ट के अन्तर्गत क्या कार्यवाही कर सकती है ? सभापति जी इस संबंध में 18 तारीख को एक न्यूज आयटम भी आया है कि--

"Cooperatives have stopped supply to DMS since 7th August demanding a hefty hike in procurement prices from Rs. 7/- to Rs. 9.40/- The Government refused to give in to the demand and has persuaded some State Federations to rush milk to the Capital."

सभापति जी मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि अभी जब इन कोआपरेटिव्ज ने डी०एम एस० को दूध देना बन्द कर दिया या कम कर दिया तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिये और दिल्ली में दूध की सप्लाई सही ढंग से हो सके इसके लिये क्या सरकार ने मिल्क फेडरेशस से बात की है ? किसी सुझाव पर यह विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी पूरी जानकारी सदन को दी जाय और यह भी बताया जाय कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्मित घी,

मक्खन की सप्लाई बनाये रखने के लिये व इन दामों पर नियंत्रण रखने के लिये आपकी सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

SHRI K. C. LENKA: There are two institutions, the DMS and the Mother Dairy that supply milk to the Delhi metropolitan city. About 10.5 lakh litres of milk is supplied to the city. Besides this, there are a number of private organisations that also supply milk to the city. The DMS procures milk from Cooperative Dairy Federations in Rajasthan, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. The hon. Member wanted to know whether these Federations have stopped their supply of milk to the city. I would like to assure the Member that these Federations have stopped supply of milk are not true. Actually, the milk producers have demanded a higher price and they have written to the DMS authorities that unless the price is increased, they would not supply milk. This has been sorted out and now they have not stopped the supply. Supply is all right.

Sir, regarding his point about milk supply, I would like to state that the demand has increased now by ten per cent and supply has generally decreased by ten per cent due to the lean season. The period, August-September, is the lean season normally and during this period the supply of milk by the producers decreases. So, with the increase in demand by ten per cent and with the decrease in supply by ten per cent, there has been some shortage of milk in the Delhi metropolitan city.

With regard to the question of conversion of milk into milk products, in order to keep the milk supply as it is, we have banned the manufacture of milk products, that is, conversion of milk into other things. We have banned it. But there is information that some people are doing that. But we are strictly prohibiting that and also, in order to keep the supply level as it is, again we are going to ban the production of milk products for two more months.

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महामना, मिल्क पाउडर बनाने के कुछ ऐसे कारखाने दिल्ली में बनाये गये जो कि अनुबंधित नहीं थे । उन्होंने कोई लायसेंस नहीं लिया । उनको आज्ञा नहीं थी । मैंने आज लिखा है कि ये कैसे चालू हुये? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? दिल्ली प्रशासन सोता क्यों रहा ? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय जोकि इनमें मिले हुये थे या जिन्होंने कनाइव किया इस बात के लिये कि ये चलते रहें ? किस तरीके से ये इनके साथ में हेराफेरी कर के इस तरह से मिल्क पाउडर बनाते रहे जबकि इजाजत इस बात की नहीं थी ।

डा० रत्नाकर पांडेय : माननीय सभापति जी, जैसा कि पहले राज्य मंत्री जी ने बताया कि दूध की 10 परसेंट मांग बढ़ी है। हम पार्लियामेंट के मेम्बर्स जब पार्लियामेंट में बटर, घी आदि मंगाते हैं तो पहले स्लिप भेज देते थे और मिल जाता था । अब वहां जाकर रजिस्टर पर दस्तखत कर के लेना पड़ता है । तो यह जो नयी-नयी अपमानजनक परंपरायें डाली गयी हैं, इनको रोका जाय । दूसरे जब संसद में ही दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा सप्लाई की जाने वाली चीजों की कमी है तो देश के साधारण नगरों की क्या स्थिति होगी, यह स्वयं माननीय सभापति जी, आप एक राष्ट्र के महान पुरुष और भारत के उपराष्ट्रपति के साथ इस सदन के माननीय सभापति होने के नाते, कल्पना कर सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा बंधन के दिन, यह सही नहीं है कि खोये की मिठाई सौ रुपये किलो, तक बेची गयी ? उसके लिये बहाना यह बनाया गया कि दूध की कमी है, दूध नहीं मिल रहा है । सभापति जी, जो प्राइवेट आर्गनाइजेशंस हैं, उनके लेबल का नाम लेकर मैं उनको विज्ञापित नहीं करना चाहता, बहुत से संस्थान हैं जो घी, दूध और दूध से बने हुये पदार्थ सप्लाई करते हैं । उनकी मात्रा भी बहुत अधिक है वह सस्ता भी है और शुद्ध भी है । इनको नियंत्रित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? सभापति जी, अभी कुछ दिन पूर्व अखबार

मेरे ने छपा कि दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे। सुरेश पचौरी जी गवाह हैं, मेरे घर में बताया कि दाम बढ़ गया है। मैंने कहा कि दाम नहीं बढ़ेंगे। दूसरे दिन पता लगा कि दाम सचमुच बढ़ गये।

श्री सभापति : तो कौन सही निकला आप दोनों में ? क्या तय हुआ, कौन जीता? आप जीते या पचौरी जी जीते ?

डा० रत्नाकर पांडेय : यह तो मंत्री जी बतायेंगे। दूध का दाम नहीं बढ़ रहा है यह एक दिन अखबार में छपता है और दूसरे दिन छपता है कि बढ़ गया है। तो इस तरह की दुविधा की स्थिति सरकार की क्यों है ? आपके दिल्ली मिल्क स्कीम के जो कंट्रोलिंग अथारिटी है, वह नैशेप आफ डाउटी करते हैं, इसलिये ऐसा होता है। उन पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और दाम नियंत्रित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसके अलावा दिल्ली मिल्क स्कीम का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेट कम्पनियां बना रही हैं, उनको रोकने के लिये और दिल्ली मिल्क स्कीम के माध्यम से सारी सप्लाई करने के लिये आप क्या ठोस उपाय कर रहे हैं, इस बारे में भी सदन को जानकारी दें ?

श्री संघप्रिय गौतम : आप तो दूध के लिये परेशान है, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं।

डा० रत्नाकर पांडेय : वह तो कल हो गया न।

SHRI K. C. LENKA: Sir, the demand on DMS products has increased because milk and its by products supplied by the DMS are available at a cheaper rate compared to the Mother Dairy and other privte organisations who are supplying to the Delhi metropolitan city. That is why pressure is more on DMS products. I do not know the position inside the Parliament House. I think, the practice which was there previously is going on. Whatever demand is there from the Cell inside the Parliament House, we are providing it. But outside the Parliament, in the milk booths, there are a number of people in the queues to get the DMS milk because it is available at a cheaper rate compared to the Mother Dairy. Again pressure has increased due to the increase of demand of edible oil in the country, and more milk is going on for producing ghee and other things. That is why DMS milk products are on available sufficiently as per the demand of the city.

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : सभापति जी, अभी विभाग मंत्री जी ने कहा कि मिल्क पाउडर कैसे बना, लेकिन परसों ही मैंने एडवरटाइजमेंट पढ़ा कि प्राइवेट कम्पनीज एडवरटाइजमेंट कर रही हैं कि मिल्क पाउडर बनाने के लिये हमें मशीन और एक्सपर्ट चाहिये, जो हों हमें सप्लाई करें। अब उन्होंने गजट में पब्लिशड कर दिया कि डेयरी इंडस्ट्रीज को डी-लाइसैंस कर दिया। मैं पोलसन डेयरी के सामने सत्याग्रह करने वाला हूं गांधी जी के कहने से आजादी से पहले और आज उसी डेयरी को हम बुला रहे हैं। इधर पोलसन वाले आयेंगे, दूसरे आयेंगे क्योंकि इन्होंने डी-लाइसैंसिंग कर दिया। तो डी-लाइसेंसिंग करने से पहले आपने जो कोआपरेटिव डेयरीज हैं, जो एन०डी०डी०बी० हैं, उनके साथ मश्विरा किया था या नहीं किया था ? और इनके आने से कोआपरेटिव डेयरीज खत्म हो जायेंगी तो आप क्या करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सभापति जी, इनका जो प्रश्न है, वह ऐसा है कि यह तो अब इंडस्ट्रियल जो पालिसी है, उसकी वजह से उन्होंने एडवरटाइजमेंट दिया है। ये कारखाने, जिनका मैंने जिक्र किया है और जिनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ये बहुत थे और हमारी तरफ से डी०एम०एस० ने दिल्ली प्रशासन को लिखा भी कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, उसके बाद भी नहीं लिया गया। आपकी यह बात भी सही है कि जब से खोला गया है, बहुत लोगों का यह मन बना है कि हम और कारखाना मिल्क पाउडर का लगायें, लेकिन इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है और दूध

की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए पूर्ण तौर से प्रयत्न किया जाएगा। जैसे हरित क्रांति आई है, वैसे ही श्वेत क्रांति के लिए भी काम करना जरूरी है क्योंकि अगर दूध हमें लोगों को पहुंचाना है तो उसके लिए डेयरी व्यापार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, गांवों में हर जगह, जैसे भी है, पशु-पालन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और उसके लिए एक विचाराधीन प्रोग्राम है जिसे पूर्णतः कार्यरूप में परिणत करने पर हम आगे बढ़ पायेंगे और आप लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक तौर पर दूध का ज्यादा प्रबंध किया जाएगा।

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : अब कोआपरेटिव का क्या होगा ?

श्री बलराम जाखड़ : देखिए, सबसे बेहतर तरीका कोआपरेटिव का ही है और कोआपरेटिव करने से गरीब आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है और उसको कुछ मिल सकता है। इसीलिए कोआपरेटिव को पूर्णतः स्वाधीनता देने के लिए और पुनर्विचार के लिए मैंने गवर्नमेंट को लिखा है।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, अभी हरेक मौसम में, विशेषकर गर्मी के मौसम में दूध की कमी आती है, जिसकी चर्चा अभी सदन में हुई और माननीय मंत्री जी ने इस ओर इंगित भी किया कि उन्होंने उद्योग मंत्रालय को इस विषय में लिखा है। दूध की कमी की समस्या का मसला मेरी दृष्टि से एक स्थाई रूप धारण करने वाला है क्योंकि जब मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डी-लाइसेंस किया, उसको लाइसेंस से मुक्त किया गया है, तो वह बहुत बड़े खरीददार होकर बाजार में दूध ले आयेंगे और यह सबकी जानकारी में है, सब मानते हैं कि दूध का प्रोसेसिंग करके उससे जो पाउडर, घी, मक्खन और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, वे ज्यादा लाभकर हैं। तो निश्चित रूप से दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए दूध की सप्लाई मार्केट में कम होने वाली है। इस संबंध में कृषि मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय को जो लिखा है क्या उस नीति में परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि नहीं किया जा रहा है तो दूध के उत्पादन के लिए डेरी उद्योग को जो प्रोत्साहन दिया जाना है उसके लिये क्या विशेष कदम उठाये जाने हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सभापति जी, कृषि उद्योग के मातहत डेरी उद्योग भी आता है, तो डेरी के लिए ज्यादा दूध देने वाले पशु, उनको आगे बढ़ाने का काम यह डेरी डिपार्टमेंट करेगा। आज इस देश में आठ मिलियन ऐसे पशु हैं जिनका क्रोस ब्रीडिंग हमने किया है, परन्तु अभी और आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पूर्णतः जो हमारी पुरानी किस्में हैं, नस्लें हैं उनको भी उसी प्रकार से प्रोत्साहन देकर उनको भी बराबर रखें और यह भी काम हमें करना है। तो दोनों बराबर बराबर चलें और उसी के लिए यह जो सहकारिता का विभाग है उसका उपयोग किया जायेगा जिसमें आप लोगों के पास में गऊ रख सकें, दूध बेच सकें, दूध के उत्पादन से उनके बच्चों का भरण पोषण हो, आपके लिये दूध का ज्यादा प्रावधान हो और दूध मिलता रहे, जिससे कि लोग हृष्ट-पुष्ट हों। इसके लिए बहुत आवश्यकता है और यह हम करने जा रहे हैं। इस बार जैसा आपने बताया, कुछ कारण से ऐसा हुआ था कि सूखा कुछ दिन चला। आपने देखा कि बरसात देर से आयी, उस वजह से ज्यादा कमी आई वरना यह भी कमी नहीं आती। अब ऊपर वाले की कृपा हो गई है, सारा हरित मामला हो गया है, दूध ज्यादा बढ़ेगा और दूध की गंगा अवश्य चलेगी।

श्री राम नरेश यादव : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि दिल्ली मिल्क स्कीम से साढ़े चार लाख लीटर दूध प्रतिदिन वितरित किया जाता है। जैसे और समस्यायें बढ़ रही हैं वैसे दूध की भी समस्या इस देश में बहुत विकराल है और विशेष रूप से . . . (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप प्रश्न कर लो, बहुत देर लग चुकी है, 17 मिनट निकल गये हैं पहले ही सवाल में।

श्री राम नरेश यादव : जिस तरह से सप्लाई बढ़ती चली जा रही है वैसे डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है और जब डिमांड बढ़ती चली जा रही है तो... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब प्रश्न करो।

श्री राम नरेश यादव : मैं वही करना चाहता हूं। इसलिए जो योजनायें बनती हैं उनके योजनाओं के माध्यम से किसी समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास भी सरकार करती है, कदम भी उठाती है, इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो दूध की आवश्यकता है, डिमांड है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस दूध उत्पादन के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या योजनायें आप दे रहे हैं ताकि इस तरह की कठिनाईयां यहां के नागरिकों के सामने न आ सकें, यह मैं जानना चाहूंगा।

SHRI K. C. LENKA: Sir the Delhi Milk Scheme is procuring milk from Rajasthan, Maharashtra, Punjab, Gujarat and from distant places and that milk is being brought to Delhi, covering such long transport and all these things. Actually we have not taken any steps to develop the periphery areas of Delhi where we can have cooperative societies to encourage keeping cows for producing milk. That step has not been taken.

MR. CHAIRMAN: You are planning to take those steps?

SHRI K. C. LENKA: Yes. In order to supply sufficient milk to the Milk Scheme we are going to encourage periphery areas where milk can be produced more and it can meet the demand of the city.

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सभापति जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि जो आज की हमारी सहकारिता है और जो सोसाइटी हमें दूध सप्लाई करती हैं मैं उनसे आश्वस्त नहीं। उनका जो मेकअप है उसको पूर्णतया वास्तव में सहकारी बनाने की मेरी इच्छा है और उसके लिए आवश्यकता है कि ग्राम किसान को जो गांव में रहने वाला है उसको जोड़ा जाये और उसके पास पशु धन ज्यादा हो जिससे हम पूरा लाभ उठा सकें, जैसे कि गुजरात में है वही पैटर्न मैं यहां बनाना चाहता हूं और उसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्णरूपेण चेष्टा की जायेगी।

*82. [*The questioner (Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare) was absent. For answer,* vide *col.* 31-32 infra.]

देश में स्क्रैप की कमी

*83. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :†**
श्री रणजीत सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिश्र धातु (ऐलॉय) इस्पात उद्योग को पर्याप्त मात्रा में स्क्रैप उपलब्ध न होने के कारण भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में उपलब्ध स्क्रैप यहां स्थापित मिनी इस्पात संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्क्रैप का वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि इस स्क्रैप के आयात की जिम्मेदारी मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा में स्क्रैप का आयात किया गया और यह आयातित मात्रा देश की कुल मांग में कितने प्रतिशत की पूर्ति करने के समर्थ है ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Sardar Jagjit Singh Aurora.